Corruption Act and Section 109 IPC. Some irregularities in the purcase of Quick Floc Polymix by Delhi Electric Supply Undertaking were also found by the Central Bureau of Investigation. No investigations have been conducted in other cases so far.

भाषात स्थिति के दौरान भ्राम्प्र प्रदेश भें व्यक्तियों की परेशान किया जाना

4211. भी मीठालाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1977 के "डैंकन हेरल्ड" मे प्रकाशित श्री जी॰ सुन्दरैया के वक्तव्य की घोर दिलाया गया है जिसमें कहां गया है कि घ्रापात् स्थिति के दौरान घांध्र प्रदेश में लगमग 350 व्यक्तियों को मौत का शिकार होना पड़ा, घौर
- (ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है भौर उस पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) . (क) जी हा श्रीमान् ।

(ख) ब्रांध्र प्रदेश सरकार के अनुसार बारोप निराधार है । आपातस्थित के दौरान पुलिश और उपपियों के बीच 30 समस्त्र मुठमेडे हुई थी, जिनमे 34 उपपत्थी मारे गये थे । आध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक मेदानिवृत्त न्यायालीय श्री बी० भागंव की सध्यक्षता में एक बांच सायोग ऐसे बारोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जा चुका है ।

धनुषुषित जातियाँ बीर धनुषुषित जनवातियाँ के व्यक्तियाँ की खिलल मारतीय सेवाओं में चर्ती

4212. भी रामचीसास सुमन : स्या बृह मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भार-तीय इजीनियरी सेवा झादि जैसी विभिन्न झखिल भारतीय सेवाझों में झनुसूचित जातियों और झनुसूचित जनजातियों के लिए पूयक-पृथक कितने प्रतिशत स्थानों का झारकण किया गया है ;
- (ख) गत तीन वर्षों में उक्त सेवाओं में धनुसूचित जातियों भीर धनुसूचित जन-जातियों के कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये भीर भर्ती किए गये कुल उम्मीदवारों में उनकी प्रतिगता क्या है ; भीर
- (ग) क्या उनके लिए निर्धारित प्रति-मतता से अनुसूचित जातियों के कम उम्मीद-वार भर्ती किये गये है और यदि हां तो आरक्षण की प्रतिशतता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?
- गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह): (क) नीन प्रखिल भारतीय सेवाघों, प्रधांत् भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में धनुसूचित जानियो तथा धनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए धारिक्षत पवों की प्रतिशतता सीधी भनीं के पटों को कमशः 15 प्रतिशत तथा 7 र्रे प्रतिशत है । भारतीय इंजीनियरी सेवा का प्रभी तक गठन नहीं किया गया है
- (ख) मर्ती कए गए व्यक्तियों की कुल मट्या में प्रनुस्चित जातियों तथा प्रनु-सूचित जनजातियों की संख्या ग्रीर उनकी प्रतिशतता:

187

'शर्सी	का वर्षे प्रमु० जा०	भा•म•से•		মাণ্যুগরীও রূপুও খনও জাও	भाग्य० सेव	
		मनु॰ जन० जा०	धनु ० जा <i>०</i>		धमु० ४१०	গণু॰ জ ণ৹ জা৹
1974	21	10	15	7	5	3
	14.5	6.9	15.9	7.4	17.2	10.3
1975	19	12	12	6	6	4
	14.6	9.2	14.6	7.3	13	8.7
1976	21	6	17	9	9	5
	15	4.3	15.9	8.4	16.7	9. 2

(ग) अनुसूचित जातियों के उम्मीव-वारों की भर्ती में कोई कमी नहीं हुई है। उनके लिए रिक्तियां निर्धारित रीस्टर के साधार पर मारिजत की जाती है। किसी वर्ष विशेष में न भरी गई रिक्तियों को, यदि कोई हों, भग्नेनीति किया जाता है भौर उन्हें बाद की परीक्षाओं के परिणामों के माधार पर भर दिया जाता है।

Central Secretariat Canteens

4213. SHRI RAMJI LAL SUMAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that most of the Departmental Canteens in the Central Secretariat are running at a loss despite subsidy and other facilities provided by the Government;
- (b) how much subsidy has been given to each canteen during the last one year and which of them are running at a loss;
- (c) whether Government propose to hand over these canteens to private contractors; and

(d) if not, what steps are taken by the Government to check malpractices and supply cheap, nutritious and better quality foodstuffs in these canteens?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH):
(a) No, Sir.

- (b) The information is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in the Library, See No. LT-776/1.
 - (c) No, Sir
- (d) A High Power Committee was set up to go into the details of the functioning of departmental/cooperative canteens functioning in Government offices. This Committee has recently submitted its report, which is under examination. With the implementation of the accepted recommendations of the High Power Committee, it is hoped that there will be substantial improvement in the working of the departmental/cooperative canteens.